www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 104 | जौनपुर शुक्रवार, 28 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

खतरे में नहीं है संविधान, बोले पूर्व सीजेआई बीआर गवई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने संविधान की भूमिका पर बेहद स्पष्ट और सारगर्भित विचार रखा। उनके जवाबों ने न सिर्फ संवैधानिक ढांचे की मजबूती पर विश्वास जताया, बल्कि देश की तीनों संस्थाओं के बीच संतुलन और जिम्मेदारी की भावना को भी रेखांकित किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने आईएएनएस से कहा, संविधान बदला नहीं जा सकता। उन्होंने आगे समझाया कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संसद संविधान की श्बेसिक स्ट्रक्चरश में कोई संशोधन नहीं कर सकती। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संविधान की मूल आत्मा को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। गवई का बयान ऐसे समय आया है जब देशभर में संवैधानिक भविष्य और संस्थाओं के अधिकारों पर बहस जारी है। पूर्व सीजेआई ने दोहराया कि भारत का संविधान बेहद मजबूत और संतुलित ढंग से तैयार किया गया है, इसलिए इसे खतरे में बताना उचित नहीं है। दूसरी ओर, जब उनसे बाबा साहेब अंबेडकर के सपने और संवैधानिक मूल्यों पर पूछा गया, तो गवई ने कहा, बाबा साहेब ने सिर्फ राजनीतिक न्याय का सपना नहीं देखा था, बल्कि उनका सपना सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी था। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी उसके साथ चले।

मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसे विंजो गेम्स के निदेशक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विंजो गेम्स ऐप के निदेशकों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी पर धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण करने और शिकायतकर्ताओं के पैन का दुरुपयोग करने का आरोप है। सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया और संबंधित न्यायाधीश के गृह कार्यालय में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की हिरासत मंजूर कर ली है और विभाग की रिमांड अर्जी पर विस्तृत बहस के लिए गुरुवार सुबह 11.30 बजे उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है। 18 नवंबर और 22 नवंबर को, ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विंजो गेम्स ऐप मामले में दिल्ली और गुड़गांव में चार स्थानों पर तलाशी ली।तलाशी के दौरान, ईडी ने कहा कि गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 505 करोड़ मूल्य की कथित अपराध आय को धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 की धारा 17 (1A) के तहत बैंक बैलेंस, बॉन्ड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में फ्रीज कर दिया गया है। इससे पहले, ईडी ने गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण और पैन के दुरुपयोग के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

पीएम मोदी ने स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। साथ ही इसके पहले उन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम–द्ध को भी दिखाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश स्पेस सेक्टर में एक ऐसा मौका देख रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज, निजी क्षेत्र भारत के स्पेस इकोसिस्टम में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति की झलक है। उन्होंने कहा कि भरोसे, क्षमता और वैल्यू के साथ भारतीय स्पेस टैलेंट ने पूरी दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अंतरिक्ष यात्रा बहुत कम संसाधन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन हमारी उम्मीदें कभी सीमित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि साइकिल पर ले जाए जाने वाले रॉकेट के एक हिस्से से, आज भारत ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक बनाने वाले के तौर पर अपनी जगह बनाई है। पीएम मोदी ने कहा, देश ने साबित कर दिया है कि हमारे सपनों की ऊंचाई रिसोर्स से नहीं, बल्कि पक्के इरादे से तय होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के पास स्पेस सेक्टर में ऐसी काबिलियत है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर, हाई–क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड–क्लास लॉन्च साइट्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली सोच है। उन्होंने इस सफलता का क्रेडिट पिछले दशक में भारत के स्पेस सेक्टर में किए गए ऐतिहासिक सुधारों को भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने इस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, ताकि स्टार्टअप और उद्योग हमारे साइंटिफिक इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकें। पिछले छह से सात सालों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को एक खुले, सहकारी और इनोवेशन–ड्रिवन डोमेन में बदल दिया है।

स्पैम कॉल को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिंतित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को साइबर शिक्षित भारत कार्यक्रम में फेक कॉल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ष्मैं जब कभी किसी आम व्यक्ति से मुलाकात करता हूं, तो अक्सर उसके जेहन में फेक कॉल को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से नजर आती है। ऐसी स्थिति में इस सवाल का उठना लाजिमी है कि क्या बैंक खाते में जमा पैसे महफूज हैं? रामनाथ कोविंद ने कहा, ष्मैं खुद कई बार स्पैम कॉल को लेकर चिंता जाहिर कर चुका हूं। इस बात की क्या गारंटी है कि लोगों के खाते में जमा पैसों में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता? पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोगों के खाते में जमा पैसों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? अब जरा इस पूरी वस्तुस्थिति को समझने के लिए आप मेरा उदाहरण ले लीजिए। मुझे हर महीने पेंशन मिलती है। मौजूदा समय में यही मेरे लिए एकमात्र पैसे का स्रोत बचा है। ऐसी स्थिति में जब कभी मेरे पास स्पैम कॉल आता है तो मैं तत्काल बैंक से टेली करता हूं और यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कहीं मेरे खाते से पैसे तो नहीं निकल गए? उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की स्थिति महज मेरे साथ ही पैदा नहीं होती है, बल्कि इस सभागार में बैठे अधिकांश लोगों की यही फिक्र रहती है। उन्होंने 'साइबर शिक्षित कार्यक्रम' में आए लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं आप लोगों को शिक्षक समझता हूं। ऐसी स्थिति में आपका एक शिक्षित होने के नाते यह कर्तव्य बन जाता है।

पीएम मोदी–शाह की मौजूदगी में नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा पर मंथन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से निपटने की रणनीतियाँ, आतंकवाद विरोधी प्रयास, नशीली दवाओं पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय हाई–प्रोफाइल सुरक्षा सम्मेलन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के 60वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं, समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। यह कार्यक्रम नए रायपुर के नए मरीन ड्राइव परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक भाग लेंगे।

इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से निपटने की रणनीति, आतंकवाद–रोधी प्रयास, नशीली दवाओं पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष के सम्मेलन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हाल के दिनों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीतियों को उल्लेखनीय सफलता मिली है।

ओडिशा यात्रा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी दो दिवसीय ओडिशा यात्रा के दौरान राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगी और ऐसा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने बताया कि राष्ट्रपति का संबोधन शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे के बीच होगा। अध्यक्ष पाढ़ी ने पुष्टि की कि मुर्मू ओडिशा विधानसभा का दौरा करने वाली और उसे संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू दोपहर दो बजे बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और 2.20 बजे राजभवन पहुंचकर कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं ओडिशा से आती हैं और पूर्व में राज्य विधानसभा की सदस्य रही हैं। वह 2000 और 2004 में मयूरभंज जिले की राइरंगपुर सीट से दो बार विधायक चुनी गई थीं। वह बीजू जनता दल–भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में 2000 से 2004 तक वाणिज्य एवं परिवहन तथा मत्स्य पालन मंत्री रहीं। उन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि मुर्मू राज्य की मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में जिस कमरा संख्या 11 से कार्य करती थीं, उसे उनकी यात्रा से पहले नवीनीकृत किया गया है और वह उस कक्ष का दौरा भी करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, राज्य के सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर भुवनेश्वर और विधानसभा के अंदर एवं आसपास विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। मुर्मू 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगी।

शिवराज सिंह चौहान ने मोगा जिले के रणसीह कलां गाँव का दौरा किया

पंजाब, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मोगा जिले के रणसीह कलां गाँव का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जनभागीदारी और कृषि नवाचार, खासकर पराली जलाने में कमी लाने में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पंजाब के कृषक समुदाय की प्रशंसा की। चौहान ने अपने एक दिवसीय दौरे की शुरुआत एक स्थानीय गुरुद्वारे में मत्था टेकने से की और फिर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कृषि पद्धतियों की समीक्षा करने के लिए खेतों की ओर रवाना हुए। मंत्री ने किसानों से बातचीत की और सीधी बुवाई, उर्वरकों के कम इस्तेमाल और पराली प्रबंधन के उनके तरीकों को समझा। पंजाब को अद्भुत बताते हुए चौहान ने कहा कि यहाँ की पंचायत में जनभागीदारी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं... मैं पंजाब के लोगों का आभारी हूँ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर आ गए हैं। इस दौरान, मंत्री ने पंचायत सदस्यों और निवासियों के साथ एक खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ पारंपरिक पंजाबी भोजन साझा किया। उन्होंने एएनआई को बताया कि पारंपरिक 'मक्के की रोटी और सरसों का साग' खाने के बाद, मेरा मन भर गया है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चौहान ने गाँव में पिछले छह वर्षों से पराली जलाने से पूरी तरह परहेज करने का जिक्र किया और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और प्रदूषण कम करने का श्रेय किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पूरे देश में समस्याएँ पैदा हुई हैं। पराली जलाने से हम मिट्टी में मौजूद जरूरी सूक्ष्मजीवों को भी मार देते हैं और प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा, इस गाँव ने पिछले छह सालों से पराली नहीं जलाई है। वे इसे मिट्टी में मिलाते हैं और सीधे बीज बोते हैं। मैं यहाँ रणसिह कलां और उनके सरपंच को इस उपलब्धि के लिए बधाई देने आया हूँ। मैं इसे पूरे भारत को दिखाना चाहता हूँ। मंत्री ने सरकारी आँकड़ों का हवाला दिया, जिसमें पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 83: की गिरावट दिखाई गई है और देश भर के किसानों से राज्य के उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह किया। स्थानीय किसान गोपाल सिंह ने चौहान को बताया कि गाँव ने पैदावार पर कोई असर डाले बिना उर्वरकों का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है।

दिल्ली सीएम ने बताया जन–सशक्ति करण का माइलस्टोन, 85 करोड़ की वापसी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा आयोजित वित्तीय जागरूकता मेगा कैंप में भाग लिया। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और नागरिकों को उनकी लावारिस जमा राशि से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में निवासियों, बैंक अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल की प्रशंसा की और पिछले एक दशक में नागरिकों में बढ़ती वित्तीय जागरूकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने बैंकिंग में आम लोगों की बड़ी भागीदारी देखी है। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता और रुचि बढ़ी है। उन्होंने शासन में बदलाव पर जोर दिया, खासकर लोगों को सीधा लाभ सुनिश्चित करने पर। गुप्ता ने कहा, ष्पहले राजनेता कहते थे कि अगर हम एक रुपया भेजते हैं, तो केवल 10 पैसे ही लोगों की भलाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के शासन में यह संभव हो गया है कि पूरा एक रुपया आम लोगों तक पहुँचे, और आप सभी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार की प्रमुख पहल श्मेरी पूँजी, मेरा अधिकारश का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह योजना सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बिना दावे वाली धनराशि, जमा राशि और म्यूचुअल फंड को उनके असली मालिकों को वापस करने पर केंद्रित है।

पेंशनर्स परिकल्प 2025 का विमोचन एवं सम्मान समारोह हुआ सम्पन्न

दैनिक देश की उपासना ब्यूरो

लखनऊ रूउत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एवं श्री शिव शंकर द्विवेदी,संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पादित पत्रिका 'पेंशनर्स परिकल्प 2025' का विमोचन दिनांक 28–11–2025 को कृषि भवन, लखनऊ के सभागार में समारोह के मुख्य अतिथि, उ.प्र. के पूर्व मुख्य सचिव एवं वर्तमान सी०ई०ओ०, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, श्री मनोज कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। समारोह में श्री के.रविन्द्र नायक जी, पूर्व प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विशिष्ट उपस्थिति थी। इस अवसर पर श्री वासुदेव खिलनानी,वरिष्ठ पेंशनर, सचिवालय सेवा को पेंशनर्स शिरोमणि,श्री बाबूलाल ,सदस्य, कार्यकारिणी,उ.प्र. सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन को श्पेंशनर्स गौरव 'एवं उत्कृष्ट साहित्यिक गति विधियों को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए श्री मुक्ति नाथ झा, वरिष्ठ अधिकारी,निजी सचिव सेवा को साहित्य क्षत्रम् सम्मानम से अंग वस्त्रम् एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर के सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों सम्मान अपनी मां जी और पिताजी की स्मृति में पेंशनर्स परिकल्प के सम्पादक, श्री शिव शंकर द्विवेदी, संयुक्त सचिव (से.नि.), उत्तर प्रदेश शासन के सौजन्य से दिये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के 07 वरिष्ठ पेंशनर्स को भी सम्मानित किया गया, जिनके नाम हैं श्री धर्मवीर सिंह,श्री गंगा प्रसाद सिंह, श्रीयुत् श्रीप्रकाश चंद्र,श्री रामनरेश त्रिपाठी,श्री गुरु प्रसाद,श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा। उल्लेखनीय है कि श्री प्रमोद कुमार शर्मा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सम्मान की श्रृंखला में पत्रिका के सम्पादक श्री सुरेन्द्र विक्रम अस्थाना एवं श्री शिव शंकर द्विवेदी भी सम्मानित हुए।

समारोह में उपस्थित पेंशनर्स को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह जी ने आग्रह किया कि पेंशनर्स स्वयं को निष्क्रिय न समझें अपितु स्वयं को अपने स्वास्थ्य तथा समाज के हित के लिए समर्पित होने की मनःस्थिति में रखें । विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री के. रविन्द्र नायक जी ने अपेक्षा व्यक्त की कि सचिवालय प्रशासन विभाग पेंशनर्स के सेवा नैवृत्तिक देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों का समय से भुगतान करने की उस व्यवस्था को आगे भी जारी रखेंगे जिसका आरम्भ उनके कार्यकाल में हुआ था। अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए महत्वपूर्ण समय निकालने वाले मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट सहित अन्य सभी पेंशनर्स का एसोसिएशन के संरक्षक श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री व अध्यक्ष श्री पी०के० शर्मा द्वारा स्वागत/सम्मान किया गया। पेंशनर्स परिकल्प, 2025 के सम्पादक श्री शिव शंकर द्विवेदी सम्पादक द्वारा पत्रिका में उपलब्ध सामग्री का उल्लेख करते हुए पत्रिका में उपलब्ध सामाग्रियों को पेंशनर्स के लिए उपयोगी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि पेंशनर्स अपने दायित्वों का पालन करने की मनोदशा में स्वयं को तत्पर रखें। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित अन्य सभी पेंशनर्स का धन्यवाद ज्ञापन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम ओझा ने किया तो समारोहों का कुशलतापूर्वक संचालन संगठन के सचिव ,श्री एन.पी.त्रिपाठी जी ने किया।

संपादकीय

लागत बनाम लाभ

अपेक्षित यह है कि सरकार खाड़ी, पश्चिम एशिया और रूस जैसे स्रोतों से एलपीजी की खरीदारी पर आने वाली लागत और अमेरिका से खरीदारी पर आने वाले खर्च का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करे। देशवासियों को यह जानने का हक है। अमेरिका से 22 लाख टन रसोई गैस खरीदने के लिए हुए सौदे को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने श्ऐतिहासिकय करार बताया और कहा कि देश की जनता को शकिफायतीय दर पर सप्लाई करने के मकसद से एलपीजी खरीदारी का एक नया स्रोत हासिल किया गया है। स्पष्टतरू उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। लेकिन हकीकत यह है कि ये फैसला अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता की मोदी सरकार की बेकरारी की मिसाल है। खुद सरकारी सूत्रों ने कहा है कि इससे अमेरिका के व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिलेगी, जो व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की शर्त है। इसके अलावा खबर है कि भारत सरकार अमेरिका से सोयाबीन और कुछ अन्य कृषि उत्पादों को खरीदने पर भी तैयार हो सकती है। बहरहाल, गौरतलब है कि एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई कमी नहीं है। भारत अब तक अपनी जरूरत अन्य स्रोतों से पूरी करता रहा है। अमेरिकी कंपनियों की तुलना में उन स्रोतों को इसलिए तरजीह मिली है, क्योंकि उनसे खरीदना भारत को किफायती पड़ता है। धारणा यह है कि अमेरिकी गैस अपेक्षाकृत महंगी होती है और उसे लाने की परिवहन लागत भी ज्यादा बैठती है। इसलिए हरदीप पुरी का दावा सहज ही देशवासियों के गले नहीं उतरेगा। अपेक्षित यह है कि सरकार खाड़ी, पश्चिम एशिया और रूस जैसे स्रोतों से खरीदारी पर आने वाली लागत और अमेरिका से खरीदारी पर आने वाले खर्च का तुलनात्मक विवरण देश के सामने प्रस्तुत करे। ताजा करार के मुताबिक अमेरिका से एलपीजी की खरीदारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां करेंगी। यानी जो भी खर्च आएगा, वह करदाताओं की जेब से चुकाया जाएगा। अतरू देश को जानने का हक है कि मोदी सरकार की विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने का कितना आर्थिक बोझ उन पर आएगा। आने वाले दिनों में लागत बनाम लाभ के ऐसे ही सवाल कृषि पैदावार की खरीदारी (अगर हुई तो) के संबंध में उठेंगे। प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि ये सारी कीमत चुकाने के बदले व्यापार एवं भू–राजनीति में भारत को क्या हासिल हो रहा है?

भारत के कामगारों के लिए नया सवेरारू आधुनिक और दूरदर्शी दौर की शुरुआत हैं

नए लेबर कोड

सुश्री वीनू जयचंद

भारत आजादी के बाद होने वाले सबसे बड़े श्रम सुधारों में से एक के करीब है। चार नई श्रम संहिताएं– वेतन संहिता (वेज कोड), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड– अब लागू हो चुके हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य पुराने और जटिल 29 केंद्रीय मजदूरी कानूनों की जगह एक सरल, तकनीक–आधारित और मजदूर–केंद्रित व्यवस्था स्थापित करना है। यह सुधार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है, जो यह दिखाता है कि भारत एक न्यायपूर्ण, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही प्रणाली आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार देती है। बिखराव से एकरूपता तक कई दशकों तक भारत में मजदूरी कानून बहुत बिखरे हुए और एक–दूसरे से ओवरलैप करते रहे। इससे उद्योगों पर भारी नियमों का बोझ पड़ा और अनुपालन करना मुश्किल हो गया। केंद्र और राज्य के अलग–अलग कधनूनों के तहत कई तरह के पंजीकरण, लाइसेंस और निरीक्षणों ने लागत बढ़ाई, मजदूरों के कल्याण से ध्यान हटाया और अक्सर उद्योग और सरकार के बीच अविश्वास पैदा किया। कधनूनों के बिखराव और अस्पष्टता के कारण लागू करने की प्रक्रिया भी कमजोर रही, जिससे एण्डक्यूयूओटीयइंस्पेक्टर राजएण्डक्यूयूओटीय जैसे मनमाने तरीके पनपे और पारदर्शिता कमजोर हुई। नई मजदूरी संहिताएं पूरे देश में परिभाषाओं और अनुपालन नियमों को एक जैसा बनाती हैं। इसके साथ ही एण्डक्यूयूओटीयवन नेशन, वन लेबर लॉएण्डक्यूयूओटीय का सिद्धांत लागू होता है। इससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को स्पष्ट, सरल और न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं का फायदा मिलता है। एकीकृत पंजीकरण और डिजिटल व्यवस्था से दोहराव खत्म होता है, प्रक्रियाएं तेज होती हैं और जवाबदेही मजबूत होती है। वेतन, लाभ और कामकाजी परिस्थितियों की एक जैसी परिभाषाएँ पूरे भारत में लागू होंगी, जिससे विवाद कम होंगे और नियमों का पालन आसान और एकसमान होगा। सीधे शब्दों में, नई मजदूरी संहिताएं पुराने, जटिल, औपनिवेशिक ढांचे को हटाकर एक सरल, प्रभावी व्यवस्था लाती हैं जो नवाचार, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। सामाजिक सुरक्षा केंद्र में मजदूरी संहिताओं की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक सुरक्षा का बड़ा विस्तार और सुधार है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में लगभग 19 प्रतिशत आबादी से बढ़कर 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो लगभग 94 करोड़ लोगों को शामिल करता है। नई मजदूरी संहिताएं इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, श्रम कानूनों के केंद्र में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को मजबूत रूप से स्थापित करती हैं। देशभर में न्यूनतम फ्लोर वेतन की व्यवस्था और सभी कर्मचारियों को अनिवार्य नियुक्ति पत्र देने जैसे प्रावधान आय सुरक्षा को बढ़ाते हैं, श्रमिकों के औपचारिकरण को आसान बनाते हैं और पूरे मजदूर बाजार में न्याय और समानता को प्रोत्साहित करते हैं। बदलती कामकाज की दुनिया को पहचानना नई संहिताएं मानती हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में कामकाज का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जहां गिग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। पहली बार, ऐसे श्रमिकों को कानूनी पहचान दी गई है और उनके लिए खास सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हिस्सा डालेंगे। राष्ट्रीय ई–श्रम पोर्टल गिग और असंगठित श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, जिससे वे अलग–अलग योजना लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें और सामाजिक सुरक्षा को एक शहर से दूसरे या एक ऐप से दूसरे ऐप पर ले जा सकें। सोचिए, कोई डिलीवरी कर्मी बिना किसी परेशानी के शहर बदल ले या ऐप बदल ले, फिर भी उसकी सामाजिक सुरक्षा जारी रहे। राज्यों के बीच काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नई संहिताओं में उन्हें लाभ एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की सुविधा, हर साल घर जाने के लिए यात्रा भत्ता और उनकी समस्याएं कम करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड कार्यस्थल की सुरक्षा के मानकों को और ऊंचा करता है, जिससे भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को मजबूती मिलती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड में लाया गया फिक्स्ड–टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान नियोक्ताओं को लचीलापन देता है, जबकि श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। महिलाएं, युवा और जनसांख्यिकीय लाभ मजदूरी संहिताओं से महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से अधिक लाभ मिलता है, जो भारत की विकास यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण समूह हैं। समान काम के लिए समान वेतन और बेहतर न्यूनतम वेतन महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करते हैं। बेहतर मातृत्व लाभ, सुरक्षित कार्यस्थल और नियंत्रित नाइट शिफ्ट की सुविधा महिलाओं के लिए अधिक अवसर और सुरक्षा प्रदान करती है।

राष्ट्रमंडल खेल 2030 और बुलेट ट्रेन यानि गुजरात में फिर से भाजपा जीतेगी

नीरज

2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) की मेजबानी अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से सौंप दी गई है जिससे गुजरात की और तेज तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम आपको बता दें कि अब अहमदाबाद–गांधीनगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार तेज होगी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली से मंजूरी के बाद गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और करई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब का निर्माण अप्रैल 2026 में शुरू होकर 2028–29 में पूरा होगा। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे देश के भविष्य का परिवर्तनकारी मॉडल बताया था। देखा जाये तो राष्ट्रमंडल खेल और बुलेट ट्रेन, दोनों बड़े प्रोजेक्ट मिलकर गुजरात को एक नई पहचान देने जा रहे हैं और साथ ही यह 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को भी लगभग सुनिश्चित करेंगे। आज गुजरात एक बार फिर परिवर्तन के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस बार यह परिवर्तन न केवल आर्थिक या विकास का है, बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारक है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और मुंबई, अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तेजी से हो रही प्रगति ने गुजरात को वैश्विक मानचित्र पर नए अवतार में पेश करना शुरू कर दिया है। यह वही गुजरात है जिसने 2001–2014 के बीच विकास के जो बीज बोए थे, वे अब अंतरराष्ट्रीय रूप लेकर सामने आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गुजरात में होने का मतलब है राज्य की खेल अधोसंरचना का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग होगी और आने वाले दशक में गुजरात को भारत की खेल राजधानी ‘(चवतजे ब्वपजंस व‍िप्दकपं) बनाने की तैयारी भी साफ दिखाई दे रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, करई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब, नए एथलीट विलेज, हाई–परफॉर्मेंस लैब, विश्वविद्यालय आधारित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गुजरात को 2030 के बाद भी स्थायी लाभ देंगे। यह वही विरासत मॉडल है जिसने लंदन 2012 और बर्मिंघम 2022 को बदल दिया। अब यही मॉडल गुजरात में दिखेगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से गुजरात में 20,000 से ज्यादा होटल कमरों की मांग, नए स्टार्टअप, पर्यटन में उछाल और 30,000 से ज्यादा नौकरियाँ बनेंगी। यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने जब पूरी दुनिया के लोग अहमदाबाद आयेंगे तो वह बाजारों से खरीदारी भी करेंगे, घूमने के लिए राज्य के विभिन्न इलाकों में भी जाएंगे जिससे गुजरात के कारोबारियों को बड़ी कमाई होना तय है। इसके साथ–साथ प्रधानमंत्री द्वारा सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण गुजरात के तेजी से बदलते परिवहन ढांचे की झलक है। 508 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ने गुजरात को देश का पहला हाई–स्पीड रेल राज्य बनाने की तैयारी पूरी कर दी है। हम आपको बता दें कि 85: से अधिक मार्ग वायाडक्ट पर है, 17 नदी पुल तैयार हैं, सूरतदृबिलिमोरा सेक्शन लगभग पूरा हो गया है और 2026 तक दो गुना क्षमता वाला ‘टच्‍ एयरपोर्ट बन जायेगा। जब मुंबईदृअहमदाबाद का सफर 2 घंटे में तय होगा, तब गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि भारत का व्यापारिक हाई–स्पीड कॉरिडोर बन जाएगा। और यही वह बिंदु है जहाँ विकास राजनीति से मिलता है। 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होंगे। जनता देखेगी कि किसके पास है एजेंडा? कौन दे सकता है भविष्य की तस्वीर? और कौन दिखा सकता है कि गुजरात सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक ‘मॉडल स्टेट’ है? यहाँ भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन, ये दोनों प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं, भावना और आकांक्षा के भी प्रतीक हैं। गुजरात का युवा इससे अपने भविष्य को जोड़ चुका है। खेल में अवसर, नौकरी में वृद्धि और तकनीकी अधोसंरचना का नया युग आने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ने 2027 की चुनावी पिच पर दो बड़े ”विकासदृसिक्सर“ पहले ही जड़ दिए हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की चमक, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का आधुनिक भारत। यह पूरा नैरेटिव भाजपा के पक्ष में एकतरफा वातावरण बनाता है। विपक्ष भले ही अपने मुद्दे तलाश रहा हो, लेकिन उसके पास इस स्तर का कोई प्रतिविकल्पी विकास मॉडल नहीं है। इसलिए निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन, दोनों मिलकर गुजरात को अगले दशक के लिए पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। यही परिवर्तन की राजनीति भाजपा को 2027 के चुनाव में एक बार फिर भारी जीत की ओर ले जाती दिखाई दे रही है। गुजरात को विकास की जो दूरदृष्टि चाहिए वह इन दो विशाल परियोजनाओं के रूप में, पहले ही भाजपा के पास है।

मुस्लिम वोट के लिए ममता का एसआईआर पर विरोध

योगेंद्र

बिहार में राजदकृकांग्रेस विपक्षी महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद पश्चिमी बंगाल में वर्ष 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चौसर बिछ गई है। इस चौसर पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई भी दाव हाथ से नहीं देना चाहती हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआइआर का जम कर विरोध कर रही है। इस विरोध की जड़ में छिपा हुआ है ममता का मुस्लिम वोट बैंक प्रेम। ममता एक तरफ अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का पुरजोर समर्थन करती रही हैं। ममता का प्रयास है कि भाजपा उत्तर भारत के राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाए। इसलिए ममता मुस्लिम वोट बैंक के खिसके बगैर हिन्दू वोट बैंक को भी साधने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल के 294 सीट के लिए मार्च–अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होना है। यह चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को राज्य की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दलों के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं भाजपा, वाम दल और कांग्रेस भी नए गठबंधनों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता एसआइआर को विरोध का राजनीतिक हथियार बना लिया है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में जब से वोटर लिस्ट के एसआईआर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद से पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। दोनों देशों में अवैध रूप से सीमापार करके आने–जाने का यह सिलसिला पहले घुसपैठियों के अलावा अधिकतर तस्करों के बीच होता था। लेकिन अब जिस तरह से भारत से बांग्लादेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे घुसपैठियों का बांग्लादेश वापस लौटना माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से लगते भारत–बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कुछ कामयाब भी हो रहे हैं। हालांकि, बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ को देखकर ऐसे लोग जंगलों में भाग जाते हैं। लेकिन बीएसएफ की नजर में ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं। जिनमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू की थी। चार दिसंबर तक वोटरों को एनुमरेशन फार्म बांटे जाने और वापस लिए जाने हैं। आयोग का कहना है कि अभी तक पश्चिम बंगाल के कुल सात करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं में से सात करोड़ 63 लाख से अधिक वोटरों को एनुमरेशन फार्म बांटे जा चुके हैं। यह काम 99 फीसदी पूरा कर लिया गया है। अब भरे गए फार्म इकट्ठा करना शुरू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग के स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन का लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी रैली के बाद बनगांव में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लेंगी। ये दूसरी एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च होगा जिसका नेतृत्व ममता करेंगी। पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में हुई थी। जबकृजब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर किसी तरह का संकट नजर आता है, ममता बनर्जी हमेशा उनके पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। बनर्जी ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश में कानून–व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण संभावित मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। ममता बनर्जी के इस बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश ने इस मामले पर अपनी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को एक खत भेजा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा था कि ‘पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरे सम्मान के साथ, जिनके साथ हमारे बहुत ही मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं, हम यह साफ करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम पैदा करने की बहुत गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक खत भेजा है। बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि रोहिंग्या शरणार्थियों की भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुल कर पैरवी की। ममता ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का किया विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है। उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता का ये बयान केंद्र द्वारा ये कहने के बाद आया था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उनके संपर्क आईएस और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से हैं। ममता ने कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या लोगों की मदद की अपील की है। हम इसका समर्थन करते हैं। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों में हडकंप मचा हुआ है। वे पहचान उजागर होने के डर से सीमा की तरफ भाग रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध कर रही हैं। इसी तरह का विरोध कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने भी बिहार में किया था। इसके बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ममता को डर है कि यदि एसआइआर का विरोध नहीं किया और अवैध शरणार्थियों में भगदड़ जारी रही तो इसका वोट बैंक पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब वोट बैंक की राजनीति के लिए राजनीतिक दल देश की एकताकृअखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की पैरवी कर रहे हैं। यह निश्चित है कि ऐसी हरकतों से बेशक चुनाव जीते जा सकते हो, किन्तु इसके दूरगामी परिणाम देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा पर पड़ते हैं। बेहतर होगा कि नेता देश के बारे सोचे और ऐसे तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की पहल करें, जिससे देश को किसी भी तरह का खतरा हो

शिखर पर धर्मध्वजा, हाशिए पर संविधान

सर्वमित्रा

धर्म का ज्ञान देने में जरा सी कसर नहीं रहना चाहिए, यही उद्देश्य मीडिया का दिखा। अच्छी बात है कि मीडिया हर घटना और प्रकरण की आदि से अंत तक सारी जानकारी दे। जो कुछ आज हो रहा है उससे अतीत कैसे जुड़ा है और भविष्य पर इसका क्या असर होगा, यह बताना भी पत्रकारों का दायित्व है। 19 वींसदी के मध्य में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि धर्म श्जनता के लिए अफीमश है – जो वंचित लोगों को वर्तमान से अलग कर देता है, तथा प्रगतिशील राजनीति में उनकी भागीदारी को कमजोर कर देता है। मार्क्स ने तब पश्चिम में धर्म का प्रभाव और गरीबों का संघर्ष देखा था। लेकिन उनकी दो सदी पहले कही गई ये बात अब भारत के संदर्भ में पूरी तरह सटीक उतर रही है। भारत में प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, छात्रों में आत्महत्या का बढ़ता चलन, पारिवारिक टूटन, महिला उत्पीड़न, अपराध, शैक्षणिक संस्थानों के स्तर में आती गिरावट, रूपए की गिरती कीमत, बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष जैसी अनेकानेक समस्याएं फन काढ़े खड़ी हैं। अखबार उठा कर देखिए तो ऐसी ही खबरें भरी पड़ी हैं। जनता ने अच्छे दिनों की उम्मीदों के बीच इनके साथ ही रहना सीख लिया है। और अब लग रहा है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए जनता को पूरी तरह धार्मिक उन्माद में झोंकने की कला में महारत हासिल कर ली है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने से ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो तमाम चौनलों ने इसे पूरा कवरेज दिया और प्रिंट मीडिया भी हिंदुत्व में रंगा नजर आया। कुछ शीर्षकों पर गौर फरमाइए– ऐसे ही शीर्षकों से अखबारों को रंगा गया है। इसके साथ ही ध्वज पर कौन से चिह्न बने हैं, उनके मतलब क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, क्यों इसी मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया, इनकी विस्तृत जानकारी दी गई है। धर्म का ज्ञान देने में जरा सी कसर नहीं रहना चाहिए, यही उद्देश्य मीडिया का दिखा। अच्छी बात है कि मीडिया हर घटना और प्रकरण की आदि से अंत तक सारी जानकारी दे। जो कुछ आज हो रहा है उससे अतीत कैसे जुड़ा है और भविष्य पर इसका क्या असर होगा, यह बताना भी पत्रकारों का दायित्व है। जैसे राम मंदिर किस तरह बना और इसके लिए देश में नए सिरे से विभाजन की रेखा कैसे खींची गई, यह जानकारी मीडिया में फिर से आना चाहिए थी। यह बताना भी जरूरी है कि इसी साल छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त पर हर मस्जिद पर, मदरसा और दरगाह पर तिरंगा लहराने का आदेश जारी किया था। इसे राष्ट्रीय एकता और गौरव के लिए जरूरी बताया था। अब तिरंगा तो एवरेस्ट से लेकर अंडमान के द्वीपों तक कहीं भी लहराए, वाकई गौरव की अनुभूति ही होती है। लेकिन आजादी के मौके पर खास तौर पर मुस्लिम धर्मस्थल पर तिरंगा लहराने का आदेश प्रकारांतर से मुस्लिमों से उनके देशभक्ति की परीक्षा लेने जैसा है, जो सरासर अन्याय और अपमान है। देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो जिन्हें इस्लाम के नाम पर बने देश में जाना था, वे चले गए। लेकिन जो नहीं गए, उन्हें पराए होने का अहसास कराने का क्या मतलब। देश पर हरेक नागरिक का समान हक है और हरेक नागरिक को समान हक भी है। लेकिन मोदी सरकार में इस हक पर बार–बार आघात हो रहा है, उस पर तुर्रा यह कि सबका साथ और सबका विकास। अगर मस्जिदों पर तिरंगा लहराने का आदेश होता है, अगर 15 अगस्त पर हर घर में तिरंगा फहराने की अपील होती है, तो राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराकर इसे सदियों का संकल्प पूरा होना क्यों कहा जा रहा है। क्या भाजपा ने सत्ता इसी मकसद से हासिल की है कि उसे हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। बता दूं कि प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराने के बाद कहा कि श्सदियों के घाव और पीड़ा आज भर रहे हैं।श इस एक वाक्य से उन्होंने फिर उस धार्मिक विभाजन की याद दिलाई जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद समाज में बनी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे कई हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर, उस पर प्रहार कर गिरा दिया। किसी भी सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना शर्मनाक होनी चाहिए थी। लेकिन भारत में तब से लेकर आज तक ऐसा जश्न मनाया जा रहा है मानो हम अब रोजाना चांद पर आवाजाही करने लगे हैं या पूरी दुनिया में हमारा दबदबा है, हमारी जनता को भोजन, पानी, आवास, बिजली, इलाज, शिक्षा किसी की दरकार नहीं है। ध्यान रहे कि बाबरी मस्जिद का मामला अदालत में कई दशक से चल रहा था। लेकिन राम मंदिर बनाने का संकल्प लिए मोदी सरकार ने जब दिल्ली संभाली तो इस मामले की सुनवाई में तेजी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद की जमीन केंद्र सरकार को दी जाती है। केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाकर वो जमीन हिन्दुओं को सौंप दे। वहां एक राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि मस्जिद को गिराना गलत था। वो एक ऐतिहासिक धरोहर थी। लेकिन इस गलती को करने वाले कौन लोग हैं और उन्हें अब तक सजा क्यों नहीं मिली, इस सवाल का कोई जवाब सरकार या अदालत के पास नहीं है। अयोध्या पर फैसला सुनाने वाले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, रिटायर होने के बाद भाजपा की मदद से राज्यसभा के सांसद बन गए और एक अन्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ बता चुके हैं कि राम मंदिर पर फैसला देने से पहले वे देवी की मूर्ति के सामने बैठे थे। ये बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन इन्हें बार–बार दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि लोग एक ऐसे अन्याय को न भूलें, जिसे भाजपा धर्म का नाम देकर जायज ठहराती है। हिंदू धर्म ने कभी नफरत की शिक्षा नहीं दी। बल्कि बाहें खोलकर हर नए विचार का स्वागत किया। किसी विचार से अगर असहमति रही तो उसे जाहिर किया, लेकिन अपने अहंकार में उसे गलत नहीं ठहराया। ऐसी उदारता और प्रगतिशीलता के कारण ही प्राचीन भारत की ख्याति फैली। हिंदू धर्म, संस्कृत के ग्रंथों की तरफ विदेशी विद्वान आकर्षित हुए। लेकिन भाजपा का धर्म विशुद्ध सत्ता की राजनीति से प्रेरित है। अयोध्या में ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्ये धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए, पर वचन न जाए अर्थात जो कहा जाए, वही किया जाए। ये धर्मध्वज संदेश देगा–कर्मप्रधान विश्व रचि राखा अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्मध्वज कामना करेगा– बैर न बिग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आसा यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति और समाज में शांति एवं सुख हो।श अभी तो पता नहीं कि खुद मोदीजी ने इस ध्वज से ऐसी कितनी प्रेरणा हासिल की। लेकिन अगर वे वाकई प्राण जाए पर वचन न जाए या भेदभाव से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो बेशक ऐसे सौ ध्वज और अपने आसपास फहरा लें, ताकि उन्हें याद रहे कि 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, देश से काले धन को मिटाने के लिए 2016 में नोटबंदी की थी, किसानों की दोगुनी आय, सबके लिए मकान, सबके लिए साफ पानी जैसे वादे किए थे। लेकिन 2025 के छठ में भी लोगों ने गंदे पानी में ही अर्घ्य दिया और खुद मोदी के लिए अलग से पानी की व्यवस्था की गई, ताकि गंदगी उन्हें बीमार न कर दे। कोरोना काल में बनाए गए पीएम केयर्स फंड का खुला हिसाब तक मोदी नहीं देते और ज्ञान देते हैं कि विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। अच्छी बातों को केवल दोहराने से अच्छाई कायम नहीं होती है, उसे व्यवहार में भी उतारना पड़ता है। फिलहाल भाजपा और खुद मोदी के व्यवहार में यह कमी साफ दिखती है। भेदभाव मुक्त समाज बनाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के उद्घाटन से लेकर राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन तक दलित, ।

नीलामी नहीं अब लॉटरी से मिलेंगे औद्योगिक भूखंड, अलग-अलग नियम और शर्तें समाप्त कर बनेगी एक नीति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंड उपलब्ध कराने के अलग–अलग नियम और शर्तें समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए एक समान नीति बनेगी। भविष्य में भूखंड आवंटन नीलामी से न होकर लॉटरी से होगा। आवंटित भूमि का इस्तेमाल उद्योग की स्थापना के लिए नहीं करने, भूमि का दुरुपयोग करने या हस्तांतरण करने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यह निर्णय बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में लघु उद्योग भारती प्रतिनिधिमंडल और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विस्तार, उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर चर्चा हुई। प्रस्तावित किया

गया कि एक ही प्रकार के उत्पादों के लिए एक ही औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन कर उद्योग क्लस्टर तैयार किए जाएं। सूक्ष्म उद्यमियों को सस्ती किस्तों पर शेड उपलब्ध कराकर प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित करने पर भी सहमति बनी। चर्चा के दौरान उद्योगों के लिए लीज रेंट न्यूनतम करने और भूखंड सरकारी भूमि पर होने पर केवल विकास व्यय ही लेने पर सहमति बनी। निजी भूमि के आवंटन में कुल लागत और विकास व्यय पर कम से कम 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का सुझाव दिया गया। जो उद्योग किराये के स्थानों पर चल रहे हैं या जो अपने उद्योगों का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी। वहीं, उद्यमियों की सुरक्षा और सुगमता के दृष्टिगत फायर एनओसी सुविधा को सामूहिक प्रणाली के माध्यम से आसान बनाने, भूखंड कब्जा अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने करने, मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया को समयबद्ध करने तथा प्रदूषण, फायर और विद्युत सुरक्षा जैसी एनओसी को मानचित्र के साथ ही सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। मंत्रियों ने कहा कि प्रीमियम और किस्तों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट आधारित व्यवस्था के अनुसार ही लिया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज न लगाकर साधारण ब्याज ही लगाया जाए। कब्जा मिलने के बाद ही ब्याज देय हो।

गुजारा भत्ता पति का दायित्व, मजदूरी करके भी पत्नी को देने होंगे पैसे

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पारिवारिक विवाद के मामले में दिए फैसले में कहा कि मजदूरी करके भी पत्नी को गुजारा देना पति का दायित्व है। बेरोजगार होने की दलील देकर पति, पत्नी के भरण पोषण से मुकर नहीं सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पति की उस आपराधिक निगरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लखनऊ के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को प्रति माह 2500 रुपए बतौर अंतरिम गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित करार दिया। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह अहम फैसला पति की निगरानी याचिका पर दिया। इसमें पति ने बीते 20 अगस्त के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले में पहले पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा दिलाए जाने की अर्जी दी थी। पत्नी की अर्जी के मुताबिक 28 नवंबर 2013 को दोनों का जालंधर, पंजाब में विवाह हुआ था। पत्नी का आरोप था कि विवाह के बाद उसके पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसपर वह 2021 में अपने भाई के साथ लखनऊ वापस आ गई। उधर, पति ने बेरोजगार होने की बात कहकर पत्नी को गुजारा न दे पाने का तर्क दिया। फैमिली कोर्ट ने यह मानते हुए कि पति सक्षम व्यक्ति है, ऐसे में यदि वह एक श्रमिक के रूप में भी काम करे तो वह प्रतिमाह 12500 रुपए न्यूनतम मजदूरी कमा सकता है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 2500 रुपए प्रतिमाह गुजारे के रूप में देने का आदेश पति को दिया था। हाईकोर्ट ने, फैमिली कोर्ट के इस आदेश में कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता न पाते हुए।

संक्षिप्त खबरें

राष्ट्रीय जंबूरी में संस्कृति-सभ्यता का समागम

लखनऊ, (संवाददाता)। बोली व भाषा अलग–अलग, संस्कृति और सभ्यता भी एक दूसरे से भिन्न, लेकिन जब विभिन्न राज्यों के करीब 20 हजार कलाकारों ने प्रस्तुति दी तो लगाा कि मानो पूरा भारत मंच पर हो। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में चल रहे 19वें राष्ट्रीय जंबूरी में बुधवार को अटल सभागार में आयोजित पीजेंट शो में यह अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका उद्घाटन करते हुए शायराना अंदाज में कहा,'तुम जो उठते हो तो उठता है जमाना सारा, तुम जो सोते हो तो सोती है मुल्क की किस्मत। खन्ना ने कहा कि स्काउट गाइड्स के अंदर भारत की विविधताओं को संरक्षित करने का भी हुनर है। आयोजकों के अनुसार पीजेंट शो राष्ट्रीय एकता और भारतीय परंपरा के गौरव का सशक्त संदेश भी देता है। सुरेश खन्ना ने सांस्कृतिक झांकियों का अवलोकन किया। पीजेंट शो में नेपाल की संस्कृति के भी रंग दिखे। वहां के कलाकारों ने अपने परिधान में सभ्यताओं को प्रदर्शित किया। यूपी, उत्तराखंड, बिहार झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों की भी प्रस्तुति शानदार रही।

संवैधानिक मूल्यों से रूबरू हुए युवा

लखनऊ, (संवाददाता)। यश फाउंडेशन की ओर से शिरोज कैफे और आंबेडकर पार्क में आयोजित संविधान कारवां युवोत्सव–2025 से युवा संवैधानिक मूल्यों से रूबरू हुए। आयोजन में लखनऊ व सीतापुर के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की शुरुआत गतिविधि से हुई। युवाओं ने न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को अनुभव के माध्यम से समझा। युवा स्टॉल, कला, खेल और संवाद सत्रों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। इंटरैक्टिव खेल कौन बनेगा संविधान चौंपियन और युवा कवियों की प्रस्तुतियों ने वाहवाही बटोरी। पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने युवा नेतृत्व पर जोर दिया। पहल संस्था से जुड़े युवाओं ने सरकारी योजनाओं, स्कूल पुनः नामांकन और लैंगिक समानता से जुड़े अपने जमीनी प्रयास साझा किए। समापन संगीत और रचनात्मक प्रस्तुतियों के साथ हुआ।

खादी के प्रति बढ़ रहा आकर्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विवि में चल रहे दस दिवसीय खादी महोत्सव में बुधवार को जूनियर किड्स फैशन शो हुआ। चार से छह वर्ष की आयु के बच्चों ने खादी परिधानों में रैंप पर कैटवॉक की। लोगों में खादी के प्रति आकर्षण बुधवार को भी देखने को मिला। लगातार खरीद जारी रही। खादी की सदरी, जैकेट, कंबल, इत्र, रेशमी साड़ियां, दरी, चादरें, अचार, मुरब्बा आदि की अच्छी बिक्री हुई। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी लोगों को खूब लुभाया। छह दिन में खादी उत्पादों का आंकड़ा 96 लाख के पार हो गया है। संचालन कार्यक्रम संयोजक दीप प्रकाश ने किया।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का औचक निरीक्षण कर उम्मीद पोर्टल की समीक्षा की

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद उम्मीद पोर्टल की प्रगति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर भी मौजूद रहे।मंत्री ने कार्यालय के सभी कक्षों का गहन निरीक्षण किया और रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों को शीघ्र डिजिटल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेज का सही ढंग से रख–रखाव किया जाना चाहिए।निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रदेशभर से आए विभिन्न वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात की और उनसे वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने मुतवल्लियों को बताया कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, बेहतर निगरानी और सुचारु प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगेगी तथा संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज, खासतौर पर पिछड़े पसमांदा मुस्लिम समाज और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जा सकेगा।निरीक्षण के बाद मंत्री ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या करीब सवा लाख के आसपास है, इसलिए प्रदेश में पोर्टल पर तेजी से पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।श्री अंसारी ने तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और मुतवल्लियों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक अभिलेख अपलोड करने तथा पोर्टल की सभी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कार्यालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।राज्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ प्रबंधन एक नए चरण में प्रवेश करेगा । और मुस्लिम समाज को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नेपाल के मंदिरों और मदरसों से स्लीपर सेल की फंडिंग, सामने आया आतंका का नया मॉड्यूल

लखनऊ, (संवाददाता)। नेपाल में बने विदेशी मंदिरों से भी स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही है। हाल ही में महराजगंज जिले से सटे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी में ऐसी गतिविधि सामने आई है, जहां चीन की एक संस्था तराई क्षेत्र में समाज कल्याण के नाम पर युवाओं को पैसे मुहैया करा रही है। इसके लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से मदद मांगी है। बहराइच से लगे नेपालगंज के मदरसे में तुर्किए की संस्था आईएचएच ने इस वर्ष करीब 20 करोड़ का फंड मुहैया कराया है। इस मदरसे से श्रावस्ती के भी कुछ लोगों का जुड़ाव मिला है। दिल्ली धमाके में तुर्किए की संलिप्तता के बाद नेपालगंज में आईएचएच की बढ़ी सक्रियता से सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ाई है। नेपाल सीमा पर काम कर चुके पूर्व आईबी अधिकारी संतोष सिंह बताते हैं कि तुर्किए के इस कट्टरपंथी एनजीओ के तार शादत से जुड़े हैं, जिसका असल काम जिहादियों की भर्ती और फिर उन्हें प्रशिक्षित करना है। सीरिया, कतर, ब्रिटेन और अमेरिका तक की आतंकी गतिविधियों में शादत की संलिप्तता मिली है। दिल्ली धमाके के बाद सफेदपोश आतंकवाद की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को भी विदेशी मंदिरों और मदरसों से स्लीपर सेल की फंडिंग की जानकारी मिली है। इसे पाकिस्तान की आईएसआई व चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (एमएसएस) का बदले पैंतरा माना जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बहराइच व श्रावस्ती में भी बीते सप्ताह दो ठिकानों को खंगाला है। महराजगंज के एक पूर्व नगर निकाय अध्यक्ष की भी जानकारी जुटाई गई है। अभी तक की जांच में संतकबीरनगर का मेहदावल, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, बलरामपुर, महराजगंज, बरेली, रायबरेली, गोंडा के साथ ही बाराबंकी बेहद संवेदनशील है। इनमें बरेली, रायबरेली और महराजगंज में लश्कर–ए–ताइबा का नेटवर्क सामने आ चुका है।

संक्षिप्त खबरें

इटौरा सर्वोदयी विद्यालय के छात्र और शिक्षक कोलंबो के लिए रवाना

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदयी विद्यालय, इटौरा एक बार फिर अपनी खेल प्रतिभा से देश का मान बढ़ाने जा रहा है। विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र रमन कुमार और व्यायाम शिक्षक हरीश चंद्र विश्व पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 में भाग लेने के लिए मंगलवार को कोलंबो (श्रीलंका) रवाना हो गए। यह प्रतियोगिता 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी, जिसमें 40 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।कक्षा 11 के छात्र रमन कुमार सब–जूनियर के 56 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लेंगे, जबकि व्यायाम शिक्षक हरीश चंद्र सीनियर वर्ग के 77 किग्रा भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। गुजरात के मैसाना और सूरत में आयोजित राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में रमन ने सब–जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरीश चंद्र ने सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ डेड लिफ्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया।उनकी इस उपलब्धि पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर विद्यालय के छात्र और शिक्षक का चयन गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि वे वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी जे राम ने भी कहा कि विद्यालय के खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचना प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रोत्साहन का परिणाम है।दोनों खिलाड़ी अब देश का परचम ऊंचा करने के उद्देश्य से कोलंबो रवाना हो चुके हैं।

लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य पेजेंट शो, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के पेजेंट शो का उद्घाटन करते हुए देश–विदेश से आए स्काउट गाइड का लखनऊ में स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आतिथ्य सत्कार भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी पूंजी है और राज्य सरकार ने सभी प्रतिभागियों को सम्मान और सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।वित्त मंत्री ने स्काउट गाइड के उत्साह, अनुशासन और सेवा–भाव की सराहना करते हुए कहा कि ''तुम जो उठते हो तो उठता है जमाना सारा, तुम जो सोते हो तो सोती है मुल्क की किस्मत।'' उन्होंने युवाओं को उज्ज्वल भविष्य और सफल जीवन की शुभकामनाएं दीं। श्री खन्ना ने भाईचारा और सेवा भावना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।श्री खन्ना ने स्काउट गाइड के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह स्वैच्छिक, शैक्षिक आंदोलन युवाओं के बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है। उन्होंने स्काउट गाइड के अनुशासन, आत्मनिर्भरता और समाज के लिए रचनात्मक भूमिका को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने भारत में स्काउट की नींव रखने वाले श्री राम जी वाजपेई का विशेष उल्लेख करते हुए उनके योगदान को याद किया।पेजेंट शो के दौरान वित्त मंत्री ने आकर्षक पुलिस बैंड प्रस्तुतियों का आनंद लिया और विभिन्न राज्यों एवं सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करती झांकियों का अवलोकन किया।

भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों का किया एलान, देर रात जारी की गई सूची

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार देर रात उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी। बुधवार

रात 14 जिलाध्यक्ष के नामों का एलान प्रदेश चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। भाजपा ने जिलाध्यक्ष का जिले स्तर पर चुनाव कराया था। इस चुनाव के बाद नामों का एलान लंबे समय से अटका हुआ था। इसी क्रम में बुधवार को 14 जिलों के अध्यक्षों का ऐलान किया गया। संगठन पर्व के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के निर्वाचन के क्रम में निम्न जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा की जाती है। लंबे समय बाद भाजपा ने बुधवार की रात 14 और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें से पांच जिलों में पुराने चेहरों को ही दुबारा मौका दिया गया है। वहीं, गंभीर आरोपों से घिरे फतेहपुर के जिलाध्यक्ष को पार्टी ने हटा दिया बता दें कि पार्टी इससे पहले 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब 98 जिलों में से 84 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। इस प्रकार वाराणसी समेत 14 जिले बचे हैं जिनके अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश भाजपा संगठन चुनाव के अधिकारी डा. महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इनमें आधे यानी सात पिछड़ा वर्ग हैं जबकि छह सामान्य वर्ग के हैं।

एक साल की बच्ची का बना आधार बेनिन देश के अफसरों ने देखी प्रक्रिया

लखनऊ, (संवाददाता)। एक साल की बच्ची को कुर्सी पर बैठाया। फोटो खींची, अभिभावक का बायोमेट्रिक लगाया और एक मिनट के भीतर उसका बाल आधार बनाकर थमा दिया। आधार बनाने की ये प्रक्रिया देखकर द रिपब्लिक ऑफ बेनिन की टीम ने इस व्यवस्था की सराहना की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के गोमतीनगर स्थित कार्यालय में बुधवार को पश्चिम अफ्रीका के देश बेनिन का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। बेनिन की नेशनल एजेंसी द आईडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन के डायरेक्टर जनरल अरिस्टाइड गाइ अदजिनाकोउ ग्नाहौई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। यूआईडीएआई के उपमहानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रतिनिधिमंडल के सामने प्रजेंटेशन दिया। इसके जरिये समझाया कि आधार किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके क्या फायदे हैं। किस तरह से थंब इंप्रेशन से व्यक्ति का पूरा डाटा सिस्टम पर आ जाता है। बैंक से लेकर व्यापार और पढ़ाई में किस तरह से लाभ हैं। एक आधार कार्ड बनाकर भी दिखाया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि आधार बेहतर और जरूरी व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था बेनिन में भी हो, इसके लिए वह समय–समय पर भारत सरकार से संपर्क करते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में भी वह जानकारी लेंगे। भविष्य में उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था बेनिन में लागू करने की बात कही।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने विजयी प्रतिभागियों को किया सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राज्य संग्रहालय में पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को विश्व धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित बहुमूल्य कृतियों का अवलोकन करते हुए प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई कृतियों की सराहना की।इस अवसर पर संविधान दिवस के पावन अवसर पर मंत्री ने संग्रहालय में उपस्थित सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से शपथ भी दिलाई। तत्पश्चात् निदेशक, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय डॉ. सृष्टि धावन ने विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान कराए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी।कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कैनवस पेंटिंग प्रतियोगिता में रिया जायसवाल को प्रथम, सर्वजीत कुमार प्रजापति को द्वितीय और निधि जायसवाल को तृतीय पुरस्कार मिला। प्रोत्साहन पुरस्कार श्रेया यादव, प्रवीण खरे, फैजा जावेद, दीप्ति अग्रवाल, अरविंद कुमार, श्वेता मेहता और अनुराग विश्वकर्मा को दिया गया।जूनियर ग्रुप चित्रकला प्रतियोगिता में खुशी कुमारी को प्रथम, शिवांगी कन्नौजिया को द्वितीय और उर्वी बरनवाल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रोत्साहन रागिनी सिंह रावत को प्रदान किए गए।

लखनऊ में डॉ. अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल का नए अत्याधुनिक नेत्र केंद्र का उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत के प्रमुख नेत्र देखभाल नेटवर्क में से एक, डॉ. अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ने आज गोमती नगर, लखनऊ में अपने नए अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। यह केंद्र ट्रिनिटी स्क्वायर, विजयपुर कॉलोनी, विभूति खंड, गोमती नगर में स्थित है। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और डॉ. अशर अग्रवाल की उपस्थिति में अस्पताल का उद्घाटन किया।लॉन्च के अवसर पर अस्पताल ने 31 दिसंबर 2025 तक सभी के लिए मुफ्त परामर्श, जाँच, चश्मों और सर्जरी पर विशेष छूट की घोषणा की। मरीज मुफ्त व्यापक नेत्र जांच के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।गोमती नगर का यह अस्पताल अत्याधुनिक नेत्र देखभाल सेवाओं का केंद्र है, जिसमें लेजर और रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी,।

लखनऊ में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को संविधान के प्रति कर्तव्यपालन का संदेश दिया

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में संविधान दिवस समारोह में उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि यहाँ के नागरिकों ने संविधान को सर्वोपरि मानकर सदैव इसका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश अपने संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ता है, उसे विकसित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।मुख्यमंत्री ने संविधान की उद्देशिका का सशपथ पाठन कराते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि संविधान का निर्माण 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो भारत की अनेकता को एकता में परिवर्तित करता है।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकार तभी संरक्षित होते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की मूल प्रति प्रत्येक घर में होनी चाहिए और इसकी प्रस्तावना का वाचन किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने बच्चों, शिक्षकों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे ईमानदारी से अपने कार्यों का पालन करते हैं, तो वह संविधान का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने समाज में विद्वेष फैलाने, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर असंतुलन पैदा करने वाले प्रयासों की निंदा की और कहा कि ऐसे कृत्य संविधान और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर से आत्मनिर्भरता की शुरुआत होगी, जिससे जनपद, प्रदेश और देश भी आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब नागरिक अपने कर्तव्यों और सुझावों के माध्यम से विकास में सक्रिय रूप से योगदान दें।समारोह में संविधान पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भाजपा विधान परिषद स्नातक क्षेत्र की सीट को बडेÞ अंतर से जीतने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी : सुरेन्द्र नारायण सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

सबसे पहले हमें अपने परिवार, मित्रों तथा परिचित परिवारों में जाकर अपेक्षित श्रेणी के मतदाता बनाने का काम सुनिश्चित करना हैरू सुरेन्द्र नारायण सिंह इस चुनाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन करना हैरू अजीत प्रजापति जौनपुर भारतीय जनता पार्टी की स्नातक चुनाव को लेकर एक बैठक दोनों जिला जौनपुर और मछली शहर की सयुक्त रूप से सीहिपुर स्थित कार्यालय पर बैठक सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की और मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेन्द्र नारायण सिंह उपस्थित रहे. सर्वप्रथम कार्यक्रम का सुभारंभ पार्टी के पुरोधा पं दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया उसके बाद वंदेमातरम गीत गाया गया। उसके उपरान्त मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया. मुख्य अतिथि ने उपस्थित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विधान परिषद स्नातक क्षेत्र की सीट को बडेÞ अंतर से जीतने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी उन्होंने कहा कि नए मतदाता बनवाने तथा मतदाताओं से सतत् सम्पर्क व संवाद करते हुए चुनाव के दिन मतदान स्थल तक मतदाता को पहुंचाने से लेकर मतगणना तक पार्टी के प्रत्येक नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता की जिम्मेंदारी तय करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जन–जन की आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर राष्ट्र के संकल्प के साथ बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपने परिवार, मित्रों तथा परिचित परिवारों में जाकर अपेक्षित श्रेणी के मतदाता बनाने का काम सुनिश्चित करना है। विधान परिषद के चुनाव में भी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता अपने–अपने क्षेत्रों में मतदाता बनाने के साथ चुनाव की अन्य जिम्मेदारियों से जुडेÞगें उन्होंने कहा कि पूर्ण विजय के संकल्प के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता विधान परिषद चुनाव जीतने के लिए जुटेंगे। जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि स्नातक शिक्षक चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मतदाता पंजीकरण अभियान में पूरी निष्ठा से जुटने का आह्वान किया मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है, इसलिए सभी कार्यकर्ता तेजी से जनसंपर्क कर योग्य मतदाताओं को जोड़ें। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने पर भी जोर दिया।स्नातक निर्वाचन भाजपा के वैचारिक आधार को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने पार्टी के हर सदस्य से अपने संपर्क क्षेत्रों, विशेषकर

विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में जाकर अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस चुनाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन बताया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री पीयूष गुप्ता ने किया उक्त अवसर पर मनोज दुबे, बृजेश सिंह, रविन्द्र सिंह राजू दादा, धनंजय कश्यप, अरविंद सिंह, संदीप तिवारी, महेंद्र यादव आमोद सिंह रणविजय सिंह एवं दोनों जिला के सयुक्त रूप मण्डल अध्यक्ष गण उपस्थित रहे.

जौनपुर में सांसद ने दिए जर्जर तार बदलने के निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युत समिति की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता सदर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने की। बैठक में मछलीशहर विधायक डॉ. रागिनी सोनकर, मल्हनी विधायक लकी यादव और शाहगंज विधायक रमेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारु बनाए रखना था। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार–विमर्श किया गया। अध्यक्ष सांसद कुशवाहा ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों को बदलने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शीघ्र सर्वे कराकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इन उपायों का लक्ष्य आगामी

ग्रीष्मकाल में जिले की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाना और आमजन को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करने देना है। जनप्रतिनिधियों ने अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आवश्यक विद्युत कार्यों की सूची सांसद के माध्यम से विद्युत विभाग को सौंपी। उन्होंने अपेक्षा की कि इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाए और समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो। इस दौरान चीफ इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025–26 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सांसद ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर अनिवार्य रूप से फीड किए जाएं। उनके फोन कॉल्स को प्राथमिकता पर रिसीव किया जाए और उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनपद की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु एक समग्र कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाएगा।इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्यगण सहित अन्य उपस्थित रहे।

पंजाब प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया

जौनपुर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 7235 पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव का शुक्रवार को जौनपुर आगमन पर राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक पत्रकार पी टी आई के रूहटा स्थिति आवास पर महासभा के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत से अभिभूत पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 7235 भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश कुमार श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजबूत हो रहा हैं और पंजाब में भी संगठन मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और कहा कि संगठन में शक्ति होती हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साधु ने कहा कि आज कायस्थ समाज को जागरूक करने की जरूरत है जब कायस्थ समाज जागरूक हो जाएगा बड़ा से बड़ा लक्ष्य साकार हो जाएगा।कायस्थ महासभा 7235 उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चन्द श्रीवास्तव दीनू भईया ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त जी के प्रेरणा से कायस्थ महासभा 7235 देश की सबसे मजबूत संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और कायस्थ हित के लिए समर्पित हैं उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में संगठन मजबूती से कार्य कर रहा हैं बाकी जिलों में जल्दी ही जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जौनपुर मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। संचालन राष्ट्रीय सचिव विनय श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। कार्यकम में राष्ट्रीय महासचिव राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जिला अध्यक्ष दयाल सरन श्रीवास्तव , ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष डॉ उमाकांत श्रीवास्तव प्रिंसिपल, राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद के जिलाध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव बबलू, अरुण श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव पत्रकार , संदीप श्रीवास्तव अरुण कुमार श्रीवास्तव, अम्बरीष श्रीवास्तव प्रियंका श्रीवास्तव, देवांश श्रीवास्तव , सूर्यांश श्रीवास्तव,आदि लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

राजकीय जुबिली इंटर कालेज लखनऊ में बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित

आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को राजकीय जुबिली इंटर कालेज लखनऊ में बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें बख्शी का तालाब इण्टर कॉलेज लखनऊ के छात्र अभय सिंह ने अपने मार्गदर्शक शिक्षक हरिश्चंद्र सिंह चौहान के साथ प्रतिभाग किया जिसमें विषय कचरा प्रबंधन पर माडल को बनाया जिसमें कचरे को जलाकर विद्युत उत्पादन करना, जलने पर प्राप्त राख का उपयोग कैसे किया जाए और उसका लाभ कैसे उठाएं और कचरे को जलाने उत्पन्न धुआं को पानी के टैंक में एकत्रित कर उस पानी से पौधों को संरक्षित करना और धुएं की ऊष्मा से सोलर पैनल को चार्ज करना। जिससे पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सकता है आज बिजली की समस्या का समाधान भी होगा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और कचरे से भी निजात मिलेगी। इस माडल को बनाने में मात्र 400 रुपये में बनाया गया है।इसका उपयोग बहुत ही आसानी से सभी जन कर सकते हैं।

एएनएम को प्रतिकूल प्रविष्टि, आशा से मांगा स्पष्टीकरण

सीतापुर, (संवाददाता)। जिलाधिकारी ने बुधवार सुबह समदापुर आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित वीएचएसएनडी सत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने पर आशा कार्यकत्री से स्पष्टीकरण तलब करते हुए एएनएम को प्रतिकूल प्रविष्ट देने के साथ ही दोनों के वेतन से 15–15 दिनों का मानदेय काटने का आदेश दिया। उन्होंने टीकाकरण का अभिलेखीकरण दुरुस्त रखने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर काम काज में सुधार न मिला तो अगली बार कड़ी कार्रवाई होगी। कसमंडा ब्लॉक के समदापुर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर बुधवार सुबह 9रू50 बजे पहुंचे। इस दौरान वीएचएसएनडी सत्र प्रियंका भारती एंव आशा कार्यकत्री रामश्री द्वारा आयोजित किया जा रहा था। डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि आंगनबाड़ी के पास उपलब्ध लॉजिस्टिम क्रियाशील नही थे। उन्होंने विगत 14 नवंबर को पीएचसी कमलापुर में हुए प्रसव केस में प्रसूता से मोबाइल पर बात करते हुए उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान एएनएम प्रियंका भारती के पास हीमोग्लोबिनोमीटर क्रियाशील नहीं पाया गया। साफ–सफाई व्यवस्था भी खराब मिली। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने एचआरपी (हाई रिस्क गर्भवती) महिलाओं से समन्वय स्थापित कर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर आशा कार्यकत्री रामश्री को स्पष्टीकरण जारी करने, एएनएम प्रियंका भारती को प्रतिकूल प्रविष्ट देने तथा 15–15 दिन का वेतन काटने के निर्देश बीपीएम को दिया।

वार्षिक समारोह में बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) सेंट थेरेसा स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक समारोह "आरोहण " का भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन 27 नवम्बर 2025 को उत्साह, सृजनात्मकता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैथोलिक डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप एवं मुख्य अतिथि डॉ. जेराल्ड जॉन मैथायस, इस्टेट मैनेजर फादर रोनाल्ड डिसूजा, स्कूल मैनेजर फादर लैंसी रेगो, प्रधानाचार्य फादर जॉन पॉल बारा, कॉर्डिनेटर मानवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में सण्डीला के सी.ओ. संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी। समारोह की शुरुआत मंगलभावना और आभार की संकल्पना को समर्पित मनमोहक प्रार्थना नृत्य से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। विद्यार्थियों ने वेलकम गीत से अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चातयह नाट्य प्रस्तुति "आरोहण" के माध्यम से एक साधारण शुरुआत से बुलंदियों तक पहुँचने की प्रेरणादायी यात्रा का मंचन किया गया। इसमें संघर्ष, उम्मीद, मेहनत और सफल होने की अटूट चाह को जीवंत रूप में दिखाया गया । "आरोहण" दर्शकों के मन में यह संदेश छोड़ गया कि सपने तभी सच होते हैं, जब हम हार मानने से इंकार कर दें।आरोहण नाटक के मध्य पर्यावरण और देशभक्ति की भावना को सजीव करती हुई प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने अपनी जगह पर खड़े होकर सराहा। आधुनिक जीवन, युवा सोच और सामाजिक संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाले समकालीन नृत्य ने भी उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य, नाटक, कोरस गायन, वाद्य–संगीत और थीम–आधारित मंचन के माध्यम से विद्यार्थियों ने कला, संस्कृति, राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण संरक्षण, करुणा, एकता और मानवीय मूल्यों का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की सृजनशीलता, आत्मविश्वास, मंचीय दक्षता एवं

विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन की प्रशंसा की। विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस सिस्टर निकिता ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अभिभावकों, शिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "आरोहण केवल एक मंच नहीं, बल्कि व्यक्तित्व–विकास, नेतृत्व, अनुशासन और मूल्यनिष्ठ शिक्षा की यात्रा है, जहाँ हर बच्चा अपनी प्रतिभा के साथ ऊँचाइयों की ओर अग्रसर होता है।" कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों, पूर्व छात्रों और गणमान्य नागरिकों ने पूरे आयोजन की सराहना की तथा इसे एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव बताया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मानवेन्द्र सिंह चौहान, रियाज अहमद, दीपक शुक्ला, मनोज मिश्रा, राजेश कुमार, श्रुति त्रिपाठी, रंजना सिंह, अंकिता गुप्ता, प्रतिमा सिंह, तसनीम फातिमा, मनीष त्रिपाठी, रुचिरा द्विवेदी, श्रुति मिश्रा, अमन ,एग्निस आदि शिक्षकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शहरी क्षेत्र के कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक संपन्न

जौनपुर । जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शहरी क्षेत्र के कम प्रगति वाले बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी ने बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों के कम वितरण के कारणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कुछ बीएलओ ने अवगत कराया कि कई मतदाताओं के सही पते उपलब्ध न होने के कारण गणना प्रपत्रों का वितरण करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद से समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित सभासदों की सहायता लें तथा ऐसे मोहल्लों में मुनादी कराते हुए चौपाल आयोजित कर गणना प्रपत्रों का वितरण कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि चौपाल के दौरान मतदाताओं को जागरूक करते हुए यह भी बताया जाए कि यदि वे गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे तो उनके नाम ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नही हो पायेगा और वे मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को विशेष गणना पुनरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में गणना प्रपत्र भरने की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण कार्य में उत्साहपूर्वक और पूर्ण निष्ठा से सहभागिता करें। उन्होंने कहा कि शूचिता पूर्ण एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें प्रत्येक बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व में भी जिलाधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीएलओ और सुपरवाइजर संगीता देवी, कुसुम निषाद, श्यामा देवी, सरिता देवी, अनीता पाल, शशिकला, प्रशान्त यादव सहित अन्य को सम्मानित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 100 से भी अधिक बीएलओ ने अब तक शत–प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है, जिन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्साहवर्धन करते हुए उनका सम्मान भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को इसी प्रकार सम्मानित किया जाएगा। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट इद्रनन्दन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र सिंह, सुपरवाइजर और बीएलओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

सपा विधायक जाहिद बेग को बड़ी राहत

भदोही, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 जनवरी 2026 नियत की है। साथ ही राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है। विधायक जाहिद बेग के घर से नौ सितंबर 2024 को एक नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इसके बाद की गई जांच के दौरान उनके घर से एक और नाबालिग नौकरानी मिली। इसपर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने ज्ञानपुर, भदोही में मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं विधायक की ओर से मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य से जवाब मांगा है।

पानी में डूबने से हुई थी होमगार्ड के बेटे की मौत

भदोही, (संवाददाता)।कोतवाली क्षेत्र के मवैया हरदोपट्टी निवासी होमगार्ड संजय यादव के बेटे सूर्यभान की मौत पानी में डूबने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। रविवार को चकवां महाबीर मंदिर के तालाब में उसका शव मिला था। पुलिस हिरासत से किशोरी को भगाने के आरोपी के भागने के मामले में कोतवाली के एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड पर कार्रवाई हो सकती है। विभागीय जांच में दोनों की लापरवाही सामने आई है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव पहले ही निलंबित हो चुके है। मवैया हरदोपट्टी निवासी होमगार्ड संजय यादव के बेटे सूर्यभान यादव के खिलाफ ज्ञानपुर के ही एक वार्ड निवासी व्यक्ति ने बेटी को भगाने के आरोप में एक नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 19 नवंबर को पुलिस ने युवती को सकुशल पकड़ लिया था। 21 नवंबर को पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को कोतवाली बुलाया था, हालांकि उसी दौरान वह वहां से भाग गया। 23 नवंबर की सुबह चकवां के पास तालाब में उसका शव मिला तो पुलिस महकमें में खलबली मच गई। कोतवाली परिसर से युवक के भागने पर सवाल उठने लगे। एसपी ने लापरवाही पर प्रभारी निरीक्षक को उसी दिन निलंबित कर दिया।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, दूसरे की हालत चिंताजनक

भदोही, (संवाददाता)। कोतवाली क्षेत्र के चौरी रोड बड़ी बाग मैदान के पास सोमवार की शाम दुर्घटना में घायल अब्दुल हक की मंगलवार की सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में दूसरे घायल आसिफ उर्फ बंगाली का ट्रामा सेंटर वाराणसी में उपचार चल रहा है। बाजार सरदार खां मोहल्ले के रफीक अंसारी ने बताया कि सोमवार की शाम करीब सात बजे चौरी रोड बड़ी बाग के पास पिकअप की टक्कर से बेटे अब्दुल हक (40) और उसके साथ बाइक पर बैठे युवक आसिफ बंगाली को सिर में चोट लग गई थी। दोनों को राजकीय एमबीएस अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराकर वाराणसी रेफर कर दिया गया था। मंगलवार की भोर में अब्दुल हक की मौत हो गई।

जमीन होने के बाद भी 42 वर्षों से अटका बस अड्डा

सीतापुर, (संवाददाता)। कस्बे में जमीन चिह्नित होने के 42 साल बाद भी परिवहन निगम के प्रस्तावित बस अड्डे का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। परिवहन निगम ने जमीन पर बस बस अड्डा बनने का बोर्ड लगवा कर छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वह विभाग के जिम्मेदारों से बात करते हैं तो वह लोग जमीनी विवाद का हवाला देकर चुप्पी साध लेते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों की मांग पर वर्ष 1980 में बस अड्डा बनाने के लिए परिवहन विभाग ने मंजूरी दी थी। इसके लिए ग्राम पंचायत की 12 बीघा जमीन परिवहन निगम के नाम दर्ज हो गई। जमीन मिलने के बाद भी विभाग की तरफ से बस अड्डा का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया, तो खाली पड़ी अधिकांश जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। दो साल पहले विभाग ने प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटवाते हुए जमीन अधिग्रहीत कर ली। इसके चारों ओर पिलर का निर्माण कराते हुए कंटीले तार लगाकर दिए गए। अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि वह रोजाना मिश्रिख के लिए आवागमन करते हैं। बसों के ठहराव का स्थान निश्चित नहीं है। चालक की जहां मर्जी होती है, वहां पर वह बस रोक देता है। इस लिए हर रोज बस पकड़ने के लिए परेशान होना पड़ता है। पंकज यादव भी दफ्तर जाने के लिए अप–डाउन करते हैं। यहां से लखनऊ, दिल्ली, हरदोई, सीतापुर मुख्याल, मिश्रिख, महोली आदि स्थानों के लिए जाने के लिए कई लोग रोडवेज बसों पर निर्भर हैं।

बाघ ने किया बछड़े का शिकार, अधखाया शव मिला

पीलीभीत, (संवाददाता)। गांव जटपुरा के समीप रणजीत सिंह के गन्ने के खेत में बाघ ने छुट्टा पशु (बछड़े) को मार डाला। घटना की सूचना पर बाघ की निगरानी के लिए टीम लगाई है। खेत के समीप दो कैमरे लगाए। तस्वीर कैद होने पर यह पता लगाया जा सके कि बाघ किस क्षेत्र का है। बाघ की चहलकदमी से आसपास के लोग दहशत में है। हरीपुर रेंज से गांव जटपुरा करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है। अक्सर वन्यजीव गांव जटपुरा की आबादी तक चहलकदमी करते हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।